रणजीत टाइम्स

इंदौर

शनिवार, 27 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 155 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

क्या मोदी कैबिनेट से बाहर होंगे धर्मेंद्र प्रधान? राघव चड्ढा समेत इन नेताओं को मिल सकता है मौका

यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चा, कई नए चेहरों की एंट्री की अटकलें

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच केंद्र की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है, जबकि कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम संभावित बदलावों की सूची में शामिल है। हालांकि, केंद्र सरकार या भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल इन दावों को केवल अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

चर्चाओं के मुताबिक संभावित फेरबदल में युवा नेताओं, महिला प्रतिनिधित्व और चुनावी राज्यों के नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है

पंजाब के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए वहां से भी नए चेहरे शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में राघव चड्ढा सहित कुछ अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन इनमें से किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसी वजह से संभावित कैबिनेट विस्तार को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल

सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार या किसी मंत्री को हटाने अथवा शामिल करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में सभी नाम और संभावित बदलाव केवल मीडिया रिपोर्टों एवं राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित हैं।

ड्रोन अटैक के खतरे से अलर्ट अमेरिका!

FBI की चेतावनी के बाद हाई सिक्योरिटी मोड में सुरक्षा एजेंसियां

छोटे ड्रोन बन रहे नई चुनौती, आसमान से हमले की आशंका

सवाल

क्या दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम इस खतरे से पूरी तरह निपट पाएगा? अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने देश पर संभावित ड्रोन हमलों के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी का मानना है कि सस्ते, आसानी से उपलब्ध और तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन अब संवेदनशील ठिकानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बनते जा रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार

आधुनिक ड्रोन आकार में छोटे होने के कारण रडार से बच सकते हैं और कम लागत में लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम हैं। हाल के वर्षों में दुनिया के कई संघर्षों में ड्रोन का व्यापक उपयोग होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ी है। हालांकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा तंत्रों में से एक है।

रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, काउंटर-ड्रोन तकनीक, मिसाइल रक्षा प्रणाली और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय के जरिए ऐसे खतरों से निपटने की तैयारी लगातार मजबूत की जा रही है। इसके बावजूद विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन अब भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

बड़ा सवाल

जब तकनीक तेजी से बदल रही है, तो क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत भी हर तरह के ड्रोन खतरे को पूरी तरह रोक सकती है, या सुरक्षा रणनीति को लगातार नए सिरे से विकसित करना होगा?

उद्धव ठाकरे को एक और झटका!

पुराने साथी ने छोड़ा साथ, बोले-'कब तक अकेला लड़ता रहूं'

शिवसेना (UBT) में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई, कोल्हापुर जिला अध्यक्ष के इस्तीफे से संगठन पर उठे सवाल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष रविकिरण इंगवले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने संगठन के भीतर मतभेद और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि "कब तक अकेला लड़ता रहूं।"

इंगवले के इस्तीफे ने एक बार फिर पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को हवा दे दी है

»» उनका बयान ऐसे समय आया है, जब शिवसेना (यूबीटी) संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इस इस्तीफे और लगाए गए आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसे असंतोष को समय रहते नहीं संभाला गया, तो इसका असर संगठन और चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है।

बड़ा सवाल

क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराज़गी है, या शिवसेना (यूबीटी) के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक हलचल तय करेगी

ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0: खनियाधाना बस स्टैंड पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फेक लोन ऐप से बचने के बताए तरीके, पंपलेट बांटकर किया जागरूक

अतुल जैन

खनियाधाना। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0" अभियान के तहत गुरुवार को थाना खनियाधाना पुलिस ने बस स्टैंड पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। थाना प्रभारी निरीक्षक केदार सिंह यादव ने पुलिस टीम के साथ आमजन को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, ओटीपी/यूपीआई फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैम, फेक लोन ऐप, फेक जॉब ऑफर, सोशल मीडिया फ्रॉड और फर्जी बैंक कस्टमर केयर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पंपलेट वितरण, नुक्कड़ सभा और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए गए।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा एवं एडीजी साइबर ए साई मनोहर के निर्देशन में प्रदेशभर में "ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0" चलाया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक असित यादव के मार्गदर्शन में जोन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के मार्गदर्शन में जिले में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर ठगों से बचने के लिए अनजान लिंक न खोलें, किसी से ओटीपी या क्यूआर कोड शेयर न करें और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से डरें नहीं। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

डिग्रियां बड़ी, लेकिन साइबर ठगों से हार! डिजिटल अरेस्ट में डॉक्टर, इंजीनियर और रिटायर्ड अफसर सबसे बड़े शिकार

95% पीड़ित उच्च शिक्षित, कानून और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर करोड़ों की ठगी; पढ़ाई नहीं, डिजिटल जागरूकता की कमी पड़ रही भारी

ग्वालियर समेत देशभर में साइबर अपराध का नया चेहरा सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सबसे ज्यादा शिकार वे लोग बन रहे हैं जिन्हें समाज सबसे जागरूक और शिक्षित मानता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कारोबारी और रिटायर्ड अधिकारी कानून के नाम पर रचे गए साइबर जाल में फंसकर अपनी जीवनभर की कमाई गंवा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट के अधिकांश मामलों में करीब 95 प्रतिशत पीड़ित उच्च शिक्षित हैं। साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों से लाखों-करोड़ों रुपये ट्रांसफर करा लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठग लोगों की शिक्षा नहीं, बल्कि उनके डर, जल्दबाजी और डिजिटल जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं। सावधानी ही बचाव है: किसी भी वीडियो कॉल पर खुद को अधिकारी बताने वाले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश नहीं दिया जाता। संदेह होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।

सवाल यही है:

क्या सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना पर्याप्त है, या डिजिटल दौर में साइबर जागरूकता भी उतनी ही जरूरी हो गई है?

आबकारी इन्दौर की कार्यवाही

कलेक्टर महोदय जिला-इन्दौर, श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार तथा *कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व एवं ADEO जहांगीर खान तथा वृत्त- बालदा कॉलोनी उप-निरीक्षक प्रियंका रानी चौरसिया एवं टीम के द्वारा दिनांक-24/06/2026 को दौराने गश्त शंका के आधार पर दशहरा मैदान रोड से दो पहिया वाहन क्रमांक-MP09-UD-6294 एक्टिवा स्कूटर गाड़ी को रुकवा कर तलाशी लेने पर 12 बोतल बैक वेंचर की विदेशी मदिरा व्हिस्की (कुल 9 बल्क लीटर) बरामद किया गया, जो अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही थी ,को विधिवत् जप्त कर कब्जे आबकारी लिया जाकर आरोपी राज सिंह पिता सोहन राजपूत के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

शराब बिक्री से दिल्ली सरकार की रिकॉर्ड कमाई, तीन महीने में आबकारी टैक्स से मिले 1,038 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग को केवल तीन महीनों में आबकारी कर (एक्साइज टैक्स) से 1,038 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 17 प्रतिशत अधिक है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, राजस्व में यह बढ़ोतरी शराब की बिक्री में वृद्धि, आबकारी चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का परिणाम है। विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई तेज करने, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और लाइसेंसधारकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया, जिससे कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आबकारी विभाग का कहना है कि बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन और डिजिटल निगरानी व्यवस्था के कारण राजस्व रिसाव में कमी आई है। इसके साथ ही राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति को व्यवस्थित बनाए रखने से भी सरकार के कर संग्रह को बढ़ावा मिला है। सरकार का मानना है कि आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, सख्त निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन के जरिए आने वाले महीनों में भी राजस्व वृद्धि की यह रफ्तार बरकरार रखी जा सकती है।

श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला सम्मेलन 30 जून को कालापीपल में, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

सूर्या परमार

जिला पदाधिकारियों का प्रवास जारी, ब्लॉक-ब्लॉक पहुंचकर पत्रकारों को सम्मेलन का दिया आमंत्रण

कालापीपल। श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन 30 जून को कालापीपल में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना 'चिंटू' एवं जिला संयुक्त सचिव संतोष सूर्या परमार लगातार जिले के विभिन्न ब्लॉकों का प्रवास कर पत्रकार साथियों से संपर्क कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं।

प्रवास के दौरान दोनों पदाधिकारियों ने कालापीपल पहुंचकर सम्मेलन की तैयारियों एवं आयोजन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, ताकि सम्मेलन भव्य एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।

जिला अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया मुख्य रूप से शामिल होंगे और पत्रकार हितों, संगठन की मजबूती तथा आगामी कार्ययोजना पर मार्गदर्शन देंगे। प्रवास के दौरान मक्सी, बेरछा, अकोदिया, पोलाय सहित विभिन्न ब्लॉकों में पत्रकार साथियों ने जिला पदाधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया तथा सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। संगठन ने जिले के सभी पत्रकार साथियों से 30 जून को कालापीपल पहुंचकर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की।

ED की बड़ी कार्रवाई: आस्था फाउंडेशन मामले में 12 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की नकदी और आभूषण जब्त

राजेश धाकड़

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के भोपाल जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 23 जून 2026 को आरोपी व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े कुल 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इसमें एक बैंक लॉकर भी शामिल था। कार्रवाई चौकसे ग्रुप से जुड़े आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की गई। यह जांच भोपाल EOW द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें जय नारायण चौकसे और अन्य लोगों पर वित्तीय अनियमितताओं, धन के दुरुपयोग और सोसायटी के फंड को कथित रूप से दूसरी संस्थाओं में ट्रांसफर करने के आरोप लगाए गए हैं।

ED के अनुसार जांच में सामने आया कि श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी, जो कई शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन करती है, उसके फंड के इस्तेमाल को लेकर जांच की जा रही है। आरोप है कि छात्रों से प्राप्त फीस, छात्रवृत्ति राशि और बैंक ऋणों से जुड़े धन का उपयोग संबंधित ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थाओं में किया गया। तलाशी के दौरान ED ने करीब 3.97 करोड़ रुपये नकद, मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण, ERP और Tally डेटा, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की। इसके अलावा करीब 3.45 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसी को मिले हैं। ED ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

मदन परमालिया के बेमिसाल साठ साल
नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा

इंदौर। समाजसेवी श्री मदन परमालिया 9 जुलाई 2026 को अपने जीवन के "साठ" साल पूर्ण कर रहे हैं। मदन परमालिया ने इन 60 साल में "बेमिसाल साठ साल" का सफर तय किया है। स्वाधीनता सेनानियों के कार्य और योगदान को समाज के समक्ष लाने में अपना अहम योगदान दिया है और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। अनेक समाजसेवी कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया है। शून्य से शुरू हुआ ये सफर अब "बेमिसाल साठ साल" में बदल गया है।

इस सफर को यादगार बनाने के लिए श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा एक नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है।आयोजक पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल हैं। ट्रस्ट के विनोद सत्यनारायण पटेल ने बताया कि इस समारोह में अनेक समाजसेवी संस्थाओं और स्नेहीजनों द्वारा समाज सेवी मदन परमालिया का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। समारोह 11 जुलाई, शनिवार को विद्यासागर स्कूल ऑडिटोरियम में सुबह 10.30 बजे से होगा। इसमें शहर की अनेक समाजसेवी संस्थाओं और स्नेहीजनों द्वारा समाज सेवी मदन परमालिया को अभिनंदन पत्र, मोमेंटो, शॉल, श्रीफल भेंट कर नागरिक अभिनंदन किया जाएगा।

दैनिक रणजीत टाइम्स
जिला एवं तहसील स्तर पर
एजेंसी देना है
अपना बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण के साथ हमें प्रेषित करें।
सम्पर्क करें
8224951278 :: 9827068888

आध्यात्म का वैज्ञानिक स्वरूप है सहजयोग ध्यान

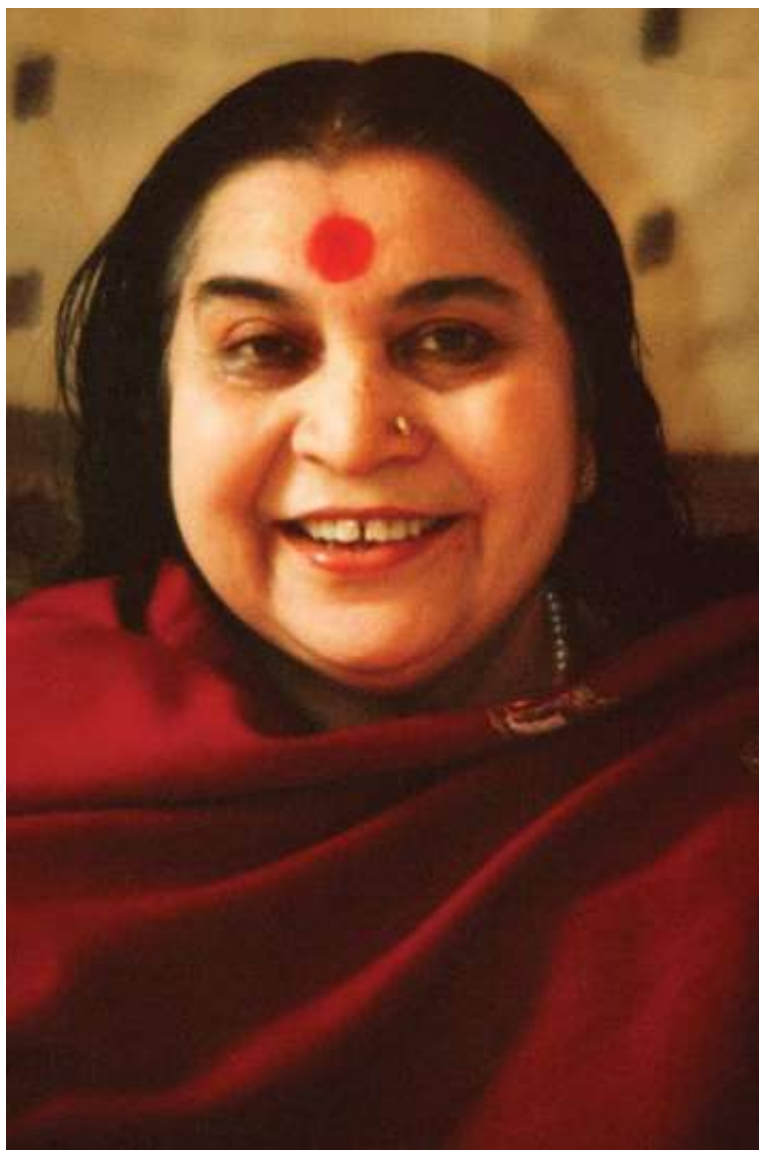

आज का मनुष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर चुका है, किंतु मानसिक तनाव, असंतोष और आंतरिक अशांति जैसी समस्याएँ निरंतर बढ़ रही हैं। ऐसे समय में सहजयोग ध्यान एक ऐसी वैज्ञानिक आध्यात्मिक पद्धति के रूप में सामने आता है, जो व्यक्ति को स्वयं के भीतर स्थित दिव्य चेतना से जोड़कर जीवन में संतुलन, शांति और आनंद का अनुभव कराता है। सहजयोग की प्रणेता परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के अनुसार, मनुष्य सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि केवल उसी के भीतर परम चेतना के जागरण की क्षमता विद्यमान है। यही जागरण अध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य है। अध्यात्म का लक्ष्य किसी मत या पंथ का प्रचार नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी दिव्य शक्तियों और सद्गुणों का विकास करना है, ताकि वह ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर अपने जीवन में प्रेम, करुणा और पवित्रता का संचार कर सके। विज्ञान जहाँ प्रकृति और पदार्थ के रहस्यों को समझकर मानव जीवन को सुविधाजनक बनाता है, वहीं अध्यात्म मनुष्य के आंतरिक जीवन को समृद्ध और संतुलित करता है। सापेक्षता सिद्धांत के जनक अल्बर्ट आइंसटीन ने भी कहा था कि विज्ञान और अध्यात्म एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। उनके अनुसार, इस सृष्टि के अद्भुत रहस्यों के पीछे एक दिव्य चेतना कार्यरत है।

चिकित्सा विज्ञान हमें शरीर की संरचना और उसके अंगों की जानकारी देता है, वहीं आत्मसाक्षात्कारी योगी अनुभव करता है कि इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म तंत्र भी विद्यमान है। यह सूक्ष्म शरीर नाड़ियों और चक्रों से निर्मित है, जिनके माध्यम से परम चेतना का प्रवाह होता है। सहजयोग ध्यान इसी सूक्ष्म तंत्र को जागृत कर व्यक्ति को आत्मसाक्षात्कार का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। इस अनुभव के पश्चात ध्यान सहज हो जाता है और व्यक्ति मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन तथा आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने लगता है। विश्व के 180 से अधिक देशों में लाखों लोग सहजयोग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और इसके माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। यह पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का शुल्क, सदस्यता अथवा अनिवार्य अनुष्ठान नहीं है। जो भी व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार एवं सहजयोग ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, वह अपने निकटतम सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800-2700-800 अथवा www.sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं।

रणजीत टाइम्स के 10 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारिका का भव्य विमोचन

रणजीत टाइम्स के सफल 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित विशेष स्मारिका (Magazine) का शुभ विमोचन इंदौर स्थित श्री रणजीत हनुमान मंदिर में मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर रणजीत टाइम्स परिवार ने भगवान श्री रणजीत हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर संस्था की निरंतर प्रगति, निष्पक्ष पत्रकारिता एवं जनसेवा के संकल्प को दोहराया।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर कथित भूमि घोटाले के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुतला दहन

सलीम हुसैन

झाबुआ मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश गंगोरिया के निर्देशानुसार एवं जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष नटवर डोडियार के नेतृत्व में जिला युवा कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवारजनों पर लगाए गए कथित 168 एकड़ भूमि घोटाले के विरोध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नटवर डोडियार ने कहा कि महाकाल की पावन भूमि पर 168 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले के माध्यम से जनता के हितों का हनन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनता की आवाज़ बुलंद करती रहेगी।

पत्रकार वार्ता के उपरांत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय के बाहर एकत्र होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के विरोध में जोरदार नारेबाजी की तथा उनके पुतले का दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कथित भूमि घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उक्त कार्यक्रम में सोशल मीडिया अध्यक्ष वसीम सैयद, जिला महासचिव हेमेंद्र (बबलू) कटारा, जिला प्रवक्ता लौकेन्द्र बिलवाल, जिला महासचिव किलू भूरिया, झाबुआ विधानसभा अध्यक्ष दरियाव सिंगाड़, थांदला विधानसभा अध्यक्ष अक्षय कामलिया, सोशल मीडिया अध्यक्ष ओवेश शेख, झाबुआ ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मेड़ा, कुंदनपुर ब्लॉक अध्यक्ष ललित परमार, कल्याणपुरा ब्लॉक अध्यक्ष सुनील निनामा, रामा ब्लॉक उपाध्यक्ष अजीत मोहनिया, आदेश भूरिया, पुनीत भानपुरिया, कमलेश बिलवाल, अनिल भाबर, मनोश गुड़िया* सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

थाना करैरा पुलिस द्वारा अबैध उत्खनन पर कार्यवाही JCB मसीन जप्त

हेमंत भार्गव

पुलिस अधीक्षक यांगचेन ड़ोलकर भुटिया के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराव की धरपकड कर जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये हैं उक्त निर्देश के पालन अति०पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26.06.2026 को थाना करैरा पुलिस को जरिए मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि देहरेटा सानी घाट पर एक जेसीवी मशीन द्वारा रेत का अबैध उत्खनन किया जा रहा है मुखबिर की सूचना से हमराह फोर्स को अवगत कराया जाकर मुखविर के बताये गये स्थान कि देहरेटा सानी घाट पर पहुंचे तो जेसीवी मशीन के द्वारा रेत का आवैध उत्खनन किया जा रहा था का मशीन का चालक पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गया मौके पर से एक JCB मशीन को विधिवत जप्त किया गया वाहन स्वामी के विरूद्ध खनिज अधि. के तहत वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण खनिज विभाग शिवपुरी के लिए भेजा गया है। प्रकरण में आरोपीगण की तलाश जारी है।

जप्ती- 01. एक JCB मशीन

सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी करैरा निरी० श्री विनोद छावई, चौकी प्रभारी उनि चेतन शर्मा, आर. हरेन्द्र गुर्जर, आर. लबकेश यादव, थाना करैरा की मुख्य भूमिका रही।

इंदौर की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

होलकर राजघराना भी ताजिए के नीचे से निकलकर मांगता था मन्नत

इंदौर। मालवा की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की पहचान केवल व्यापार, खानपान और आधुनिक विकास तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह शहर अपनी गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत परंपराओं के लिए भी देशभर में जाना जाता है। इन्हीं परंपराओं में एक विशेष परंपरा मोहर्रम के अवसर पर निकलने वाले ताजियों से जुड़ी रही है, जिसमें होलकर राजघराने की भागीदारी अपने आप में एक अनोखा उदाहरण मानी जाती है। कहा जाता है कि इंदौर में वर्षों पहले यह मान्यता प्रचलित थी कि ताजिए के नीचे से गुजरने पर मन्नतें पूरी होती हैं और जीवन की कठिनाइयों से राहत मिलती है। यही कारण था कि आम जनता के साथ-साथ होलकर राजघराने के सदस्य भी इस धार्मिक परंपरा में शामिल होते थे।

इतिहासकारों और पुराने शहरवासियों के अनुसार, होलकर शासनकाल में मोहर्रम केवल मुस्लिम समाज का धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह पूरे शहर का साझा उत्सव बन चुका था। उस दौर में महाराजा स्वयं इस आयोजन में भाग लेते थे और पूरी श्रद्धा के साथ ताजिए के नीचे से गुजरते थे। यह दृश्य इंदौर की सामाजिक एकता और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता था। उस समय यह संदेश भी दिया जाता था कि आस्था की कोई सीमाएं नहीं होतीं और इंसानियत सबसे ऊपर है। पुराने दस्तावेजों और बुजुर्गों की स्मृतियों के अनुसार, इंदौर का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख ताजिया "सरकारी ताजिया" कहलाता था। यह ताजिया आकार में अत्यंत विशाल होता था और इसकी ऊंचाई इतनी अधिक होती थी कि उसे संभालने के लिए मजबूत रस्सियों का सहारा लिया जाता था। ताजिए को संतुलित रखने और उसे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कई लोग साथ चलते थे। इस ताजिए के निर्माण की जिम्मेदारी शहर के प्रसिद्ध कारीगरों पर होती थी, जिनकी पीढ़ियां इस परंपरा को आगे बढ़ाती आईं।

बताया जाता है कि शुरुआत में इस सरकारी ताजिए का निर्माण ख्वाजाबख्श किया करते थे। उनके बाद उनके पुत्र यासिन बाबा ने इस जिम्मेदारी को संभाला और आज भी उनकी अगली पीढ़ियां इमामबाड़े में इस ताजिए का निर्माण करती हैं। यह केवल एक कला नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है, जिसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाया जा रहा है। मोहर्रम के दौरान जब सरकारी ताजिया निकलता था, तब होलकर महाराजा स्वयं वहां पहुंचते थे। वे विशेष रूप से "सैली" पहनते थे, जो उस समय की एक धार्मिक और पारंपरिक पोशाक मानी जाती थी। इसके बाद वे फातिहा पढ़वाते थे और ताजिए की सलामती व शहर की खुशहाली के लिए दुआ करते थे।

इंदौर में मुहर्रम मेले पर टकराव

महापौर की मनाही के बावजूद निगमायुक्त ने दी अनुमति, MIC ने किया फैसला निरस्त

धोबी घाट पर मुहर्रम मेले की अनुमति को लेकर नगर निगम में मतभेद खुलकर सामने आए, महापौर के विरोध के बाद एमआईसी ने निगमायुक्त के आदेश को पलटा इंदौर में धोबी घाट पर प्रस्तावित मुहर्रम मेले को लेकर नगर निगम के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव सामने आ गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा मेले की अनुमति नहीं देने के निर्देश के बावजूद निगमायुक्त ने अनुमति जारी कर दी। इसके बाद मामला महापौर परिषद (MIC) तक पहुंचा, जहां निगमायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही महापौर ने स्पष्ट रूप से मेले की अनुमति नहीं देने की बात कही थी। इसके बावजूद निगमायुक्त द्वारा अनुमति जारी किए जाने से विवाद गहरा गया। बाद में एमआईसी की बैठक में इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए अनुमति रद्द करने का फैसला लिया गया। अब यह मामला नगर निगम में अधिकारों के दायरे और निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं, मुहर्रम मेले के आयोजन को लेकर अंतिम स्थिति प्रशासन के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी।

पश्चिमी इंदौर की उड़ान!

2,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, देश का अगला लॉजिस्टिक्स हब बनने की ओर शहर

वेयरहाउस, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर; निवेश, रोजगार और कारोबार को मिलेगा बड़ा बूस्ट पश्चिमी इंदौर तेजी से देश के उभरते लॉजिस्टिक्स हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली विभिन्न लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम जारी है, जिससे इंदौर की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं में आधुनिक वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रांसपोर्ट हब और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इससे माल परिवहन अधिक तेज और व्यवस्थित होगा, उद्योगों की लागत कम होगी और निवेशकों के लिए इंदौर की आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, पश्चिमी इंदौर प्रदेश ही नहीं, बल्कि मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक और वितरण केंद्र के रूप में भी उभर सकता है।

बड़ी तस्वीर

लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में यह निवेश आने वाले वर्षों में इंदौर को औद्योगिक विकास, निर्यात, ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

‘रुक जाओ नहीं तो मार दूंगा गोली’

शिवपुरी। मध्यप्रदेश खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले के ग्राम सड़बूड़ रोड पर सिंध नदी के समीप अवैध खनन को रोकने पहुंची राजस्व टीम पर (तहसीलदार) माफिया द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी उसके पिता और बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

दरअसल बदरवास सिंध नदी के पास शासकीय भूमि पर अवैध खनन की सूचना पर तहसीलदार सचिन भार्गव, पटवारी, कोटवार और शासकीय वाहन चालक सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। टीम ने देखा कि रेत उत्खनन का रास्ता बनाने के लिए एक हाइड्रा मशीन और दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अवैध रूप से मिट्टी खोदी जा रही है। अधिकारियों ने वाहनों को जब्ती की कार्रवाई शुरू की, इसी दौरान आरोपी जयमंडल यादव उसके पिता लाखन और पुत्र विकुल ने टीम को घेर लिया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार जयमंडल यादव ने तहसीलदार को धमकाते हुए कहा, “रुक जाइए, नहीं तो गोली मार दूंगा, जेल चला जाऊंगा।”

इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने बेटे को घर से बंदूक लाने के लिए भी कहा, ताकि राजस्व अमले पर हमला किया जा सके। हंगामे के बीच आरोपी मौके से एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को भगाने में सफल रहे हालांकि, टीम ने मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पुलिस के सुपुर्द किया।

कोटवार की रिपोर्ट पर से आरोपी जयमंडल, लाखन और विकुल यादव पर BNS की विभिन्न धाराओं तथा खान एवं खनिज अधिनियम के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की है।

सिंगरौली में रेत के खेल का बड़ा खुलासा!

सिंगरौली। सिंगरौली में रेत के अवैध कारोबार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि जिले में रेत के खेल में रसूखदारों का संरक्षण हासिल है। सिंगरौली विधायक के पुत्र और दामाद पर भी रेत चोरी के आरोप लगाए गए हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच अभियान तेज कर दिया है।राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम जब मैदान में उतरी तो रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक मौके से वाहन छोड़कर भाग निकले। इसी बीच एक हाइवा ने प्रशासन की जांच को और गंभीर बना दिया। जांच में सामने आया कि हाइवा में लगी ट्रांजिट पास यानी टीपी सिंगरौली की नहीं बल्कि करीब 900 किलोमीटर दूर बुरहानपुर जिले की थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक जिले की टीपी दूसरे जिले में कैसे इस्तेमाल हो रही थी? क्या यह सिस्टम की लापरवाही है या फिर रेत परिवहन के नाम पर चल रहा कोई बड़ा फर्जीवाड़ा।सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टीपी सही थी तो वाहन इतनी लंबी दूरी तय कर सिंगरौली कैसे पहुंचा? और अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी थी तो इसके पीछे कौन लोग हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अवैध खनन या परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सिंगरौली में रेत के कारोबार और उसमें शामिल प्रभावशाली लोगों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रेत की टीपी बुरहानपुर की, वाहन सिंगरौली में... आखिर किसके इशारे पर चल रहा था यह खेल जांच के बाद ही खुलेगा रेत के इस रहस्य का राज।

छत्तीसगढ़ के 6,800 से ज्यादा निजी स्कूलों को बड़ी राहत, अब जमीन नहीं तो भी मिलेगी मान्यता

छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए मान्यता संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब निजी स्कूलों के लिए खेल मैदान, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं के लिए स्वयं की जमीन होना अनिवार्य नहीं रहेगा। यदि ये सुविधाएं स्कूल परिसर में उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी सरकारी संस्थान, नगर निगम, पंचायत या पहले से मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ वैध अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कर उनका उपयोग किया जा सकेगा।

इस फैसले से राज्य के 6,800 से अधिक निजी स्कूलों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले जमीन संबंधी शर्तों के कारण कई स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना स्कूलों की जिम्मेदारी रहेगी। संबंधित सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के वास्तविक उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा विभाग समय-समय पर इसका निरीक्षण भी करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ कम करना, शहरी क्षेत्रों में जमीन की कमी जैसी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना और अधिक से अधिक स्कूलों को नियमानुसार संचालित होने का अवसर देना है।

मोहर्रम जुलूस में वैन ब्लास्ट से सनसनी! तीन आरोपी गिरफ्तार, जुलूस निकालकर किया पेश, अब NSA की तैयारी

उज्जैन में विस्फोट मामले की हर एंगल से जांच, पुलिस खंगाल रही आरोपियों का मकसद; सख्त कार्रवाई के संकेत उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी के बाद

पुलिस ने तीनों का जुलूस भी निकाला और अब उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह पता लगाना है कि विस्फोट के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। इसके लिए तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के साथ-साथ आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह लापरवाही का मामला था या किसी सुनियोजित साजिश का।

बड़ा सवालः

क्या यह महज एक आपराधिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा।

जबलपुर में हैवानियत!

किशोरियों का कथित अपहरण, मारपीट और वीडियो वायरल; कार्रवाई में देरी पर पुलिस पर सवाल

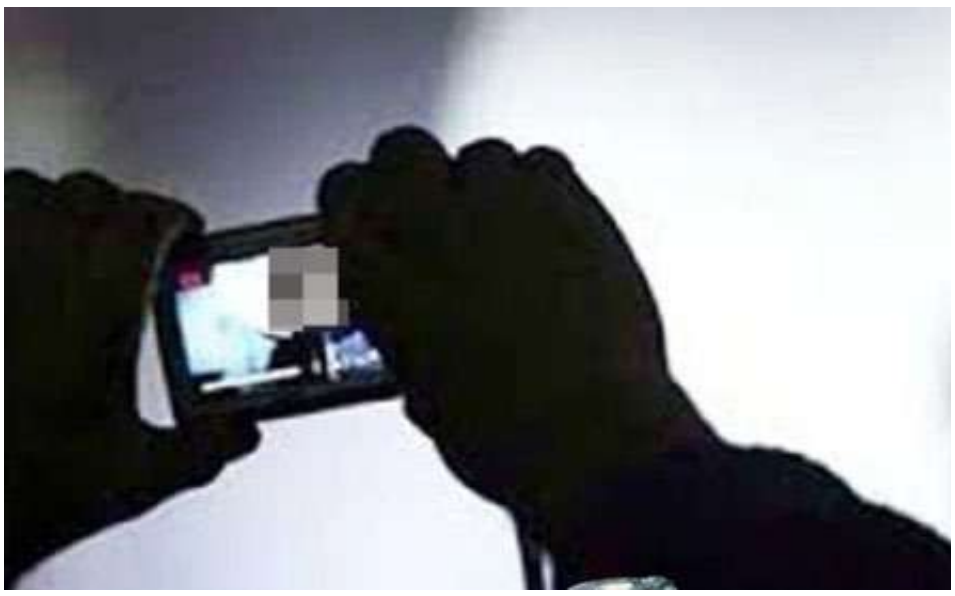

महिलाओं के एक समूह पर किशोरियों के साथ मारपीट, कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने का आरोप; परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल मध्यप्रदेश के जबलपुर से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है।

आरोप है कि कुछ किशोरियों को कथित तौर पर अगवा कर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें अपमानित करते हुए उनके कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया गया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आई है। पीड़ित पक्ष के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले स्थानीय ग्वारीघाट थाने में शिकायत की, लेकिन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख करना पड़ा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बड़ा सवाल

क्या महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के मामलों में शुरुआती स्तर पर त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित हो पा रही है, या देरी से पीड़ितों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है?

रिटायरमेंट के बाद भी दो साल नौकरी!

सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने के आरोप में उज्जैन के अधिकारियों पर जांच

60 वर्ष की आयु पूरी होने के बावजूद कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखा, वेतन-भत्तों के भुगतान पर उठे सवाल; जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में उज्जैन में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है।

आरोप है कि

दो कर्मचारियों को निर्धारित 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने के बाद भी करीब दो वर्ष तक सेवा में बनाए रखा गया। इस दौरान उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ और अन्य वित्तीय भुगतान भी दिए गए। मामले के सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नियमों की अनदेखी कर कर्मचारियों को सेवा जारी रखने की अनुमति देने और वित्तीय लाभ दिलाने के आरोपों की जांच की जा रही है। यदि जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ वित्तीय नुकसान की वसूली भी की जा सकती है।

बड़ा सवाल

क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही थी या नियमों की अनदेखी कर किसी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया? अब इसका जवाब जांच रिपोर्ट तय करेगी।

ED ने 1,200 करोड़ रुपये के SBI धोखाधड़ी मामले में 3.66 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ज़ब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के भोपाल ज़ोनल ऑफिस ने M/s एडवांटेज ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में लगभग 3.66 करोड़ रुपये की विदेशी निवेश-लिंक्ड दो जीवन बीमा पॉलिसी को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है।

ज़ब्त की गई पॉलिसी ज़्यूरिख़ इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड के पास हैं और इनकी कुल सरेंडर वैल्यू 387,814.42 USD (लगभग 3.66 करोड़ रुपये) है। ED की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ज़ब्ती प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

ED ने CBI के बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल (BSFB), नई दिल्ली द्वारा AOPL, उसके निदेशकों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी वाले मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को 1,266.63

करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया। PMLA जांच के दौरान, ED ने पाया कि AOPL और उसके प्रमोटरों ने फर्जी मर्चेंटिंग ट्रांज़ैक्शन करके, सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल होकर, व्यापारिक दस्तावेज़ों में हेराफेरी करके और बैंक फंड को विभिन्न घरेलू और विदेशी संस्थाओं में डायवर्ट करके धोखाधड़ी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाया था। ED ने कहा कि अपराध से हुई कमाई को कथित तौर पर श्रीकांत भासी द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया और भारत और विदेश दोनों जगहों पर चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

ED की जांच से पता चला कि ये दो बीमा पॉलिसी कथित अपराध के समय के दौरान श्रीकांत भासी के नाम पर ली गई थीं और बनाए रखी गई थीं। इन पॉलिसी के लिए फंड उनके विदेशी खातों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के ज़रिए दिया गया था। अप्रैल 2026 में, श्रीकांत भासी ने दोनों पॉलिसी को सरेंडर करने और उससे मिलने वाली रकम को अपने भारतीय बैंक खाते में भेजने का अनुरोध किया था। अपराध से हुई कमाई को खत्म होने से बचाने के लिए, ED ने PMLA की धारा 5(1) के तहत पॉलिसी को ज़ब्त कर लिया। इस मामले में यह सबसे ताज़ा ज़ब्ती है। इससे पहले, ED ने दुबई (UAE) में लगभग 51.70 करोड़ रुपये की नौ अचल संपत्तियों और देश में लगभग 111 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया था। यह कार्रवाई कथित धोखाधड़ी से हुई अवैध कमाई का पता लगाने और उसे ज़ब्त करने की एजेंसी की चल रही कोशिशों का हिस्सा है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व जीतू पटवारी की अगवानी में अशोक सैनी के नेतृत्व में चोरल में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ हजारों माता बहनों ने निकाली भव्य कलश चुनरी यात्रा

महू-इंदौर- जिला कांग्रेस प्रवक्ता जुगनू जादवसिंह धनावत ने बताया चोरल के सरपंच ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व जीतू पटवारी की अगवानी में चोरल में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ हजारों माता बहनों ने निकाली भव्य कलश चुनरी यात्रा।खेतों में सोयाबीन की बोवनी का कार्य चल रहा है फिर भी हजारों की संख्या में वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ताओं और माता बहनों ने भव्य चुनरी कलश यात्रा व कार्यकर्ता सम्मेलन मैं शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा अशोक सैनी के पिता भगवान दास सैनी की सातवीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नमन करता हूं साथ अशोक सैनी व उनके पिता ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हमेशा गरीबों की मदद की है आज भाजपा सरकार के शासन में किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी हर वर्ग बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा किसानों को खाद नहीं मिल रहा, फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में नंबर वन है। स्वागत भाषण सरपंच अशोक सैनी ने दिया। साथ ही अशोक सैनी ने 26 जनवरी पर घोषणा की थी की जो विद्यार्थी दसवीं व 12वीं में प्रथम स्थान पर आएगा उसे में लैपटॉप दूंगा तो आज उन्होंने अपना वादा पूर्ण कर

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों से 12वीं कक्षा में प्रथम प्रियंका पिता विक्रम और दसवीं कक्षा में प्रथम अर्जिता ओसारी पिता मनीराम को लैपटॉप अपनी ओर से प्रोत्साहन स्वरूप दिया।इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश सेवादल अध्यक्ष अवनीश भार्गव, पूर्व प्रदेश सेवादल अध्यक्ष योगेश यादव,जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सदाशिव यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाशदत्त पांडे,जिला पंचायत सदस्य कन्हैयालाल ठाकुर, मुजीब कुरैशी, रुमा भूरू भाई, रुकमणी निनामा, दिनेश सलवाडिया, शैलेश जाट, शक्तिसिंह गोयल, जीतू ठाकुर,राजेश पाटीदार, सत्यनारायण मालवीय, जनपद सदस्य अशोक आंजना, मनीष वर्मा,विलिन पाटीदार, विष्णु हारोड़, हुकम आंजना, अजय सगर, सुनील बंसल, शैलेंद्र जाट,नारायण पटेल, बैकुंठ पटेल, सेवाराम पूर्व सरपंच, पीसी हरोड़े, नितेश राजुरिया, मंसूर भाई, रशीद पटेल, विनोद पटेल, ओम पटेल, कैलाश गोयल,हफीज खान ,उमराव सिंह, सुरेश बारोड़, संतोष खराड़ी, महेंद्र पटेल, किशन पटेल,सतीश पटेल , संतोष कौशल, राकेश मकवाना, आसाराम बारूड़, काव्यांश सैनी, गिरीश सैनी, अंकित सैनी,अभयसिंह जयमल, धर्मेंद्र सैनी, संतोष चौहान, ओंकार सैनी, गोविंद शर्मा,रामचंद्र कौशल, दिनेश सैनी, बाबूलाल सैनी, हरिराम चौहान, किशोर बिलाल, विवेक सकोरिया, अरुण गुर्जर, अभिषेक यादव, जगदीश राठौर, मुन्नालाल वर्मा, नरेश जोशी, अजय वर्मा,शुभम जैन, सदाशिव चौधरी, भगवान चौधरी, राकेश पाटीदार, घनश्याम यादव, नरेंद्र मीणा, गोविंद टेलर,अलंकार यादव, लक्ष्मीनारायण कौशल, प्रदीप कौशल, सुनील कौशल, मेवालाल, राजू पटेल, भाया पटेल, मनोज गोडाले, जबर भाई, प्रवीण पाटील, राहुल जिराती,इत्यादि उपस्थित रहे और चोरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय भगवान दास सैनी की सातवीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता जुगनू जादवसिंह धनावत ने किया और आभार जिला सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सलवाडिया ने माना।

इंटर्नशिप का सुरक्षित माहौलः शिक्षा संस्थानों की साझा जिम्मेदारी

उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और पेशेवर जीवन की नींव भी होती है। विशेष रूप से कानून, चिकित्सा, पत्रकारिता और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इंटर्नशिप का वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर हो।

शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध विश्वास, मार्गदर्शन और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों से सीखने, सलाह लेने और करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर शैक्षणिक संस्थान ऐसी व्यवस्था विकसित करे, जहाँ किसी भी छात्र या छात्रा को असहज, असुरक्षित या दबावपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े। आज के समय में अधिकांश शिक्षण संस्थानों में शिकायत निवारण की व्यवस्था और महिला सुरक्षा से जुड़े नियम मौजूद हैं। लेकिन केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना, शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई करना और गोपनीयता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों का संस्थान पर विश्वास मजबूत होता है।

साथ ही, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी शिकायत या आरोप पर बिना जांच पूरी हुए किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित नहीं है। निष्पक्ष जांच, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर किसी भी न्यायपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला हैं। समाज और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि तथ्यों की पुष्टि से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुँचे। एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण वही है जहाँ विद्यार्थी बिना भय के सीख सकें, शिक्षक सम्मान के साथ अपना दायित्व निभाएँ और किसी भी प्रकार की शिकायत का समाधान निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करना है। यह लेख शिक्षा संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी वातावरण की आवश्यकता पर सामान्य विचार प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या घटना पर टिप्पणी करना अथवा किसी आरोप की पुष्टि करना नहीं है।

अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, तीन आरोपी गिरफ्तार

हेमंत भार्गव

कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर संयुक्त अमले ने की त्वरित कार्यवाही

शिवपुरी 26 जून 2026- जिले में शासकीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देश पर बदरवास तहसील के ग्राम सडबूढ़ स्थित सिंध नदी

घाट पर अवैध मिट्टी उत्खनन और शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। तहसीलदार श्री सचिन भार्गव द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के दौरान कुछ लोगों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकी देने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। तत्काल पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई और राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के संयुक्त अमले ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की।

कार्यवाही के दौरान तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अवैध उत्खनन की जांच कर प्रकरण तैयार किया गया तथा नदी घाट तक बनाए गए अवैध रास्ते को नष्ट कर दिया गया। आरोपियों के कब्जे से बरामद हथियार को जब्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवाते हुए उसे जमींदोज कराया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध उत्खनन एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना तथा शासकीय भूमि को अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।